Bharat International Journal of Humanities and Social Sciences | 2013 | Volume 02 | Issue 02 | Pages 01-06
https://bijhss-university-journal.in/en

Bharat International Journal of Humanities and Social Sciences

Research Article

प्रथम भारत–पाकिस्तान युद्ध (1947–1948): कश्मीर विवाद की उत्पत्ति, युद्ध का घटनाक्रम और राजनीतिक परिणाम

The First India–Pakistan War (1947–1948): Origins of the Kashmir Dispute, Course of the War, and Political Consequences

Prof. Mahima Mangal[1]

[1]Assistant Senior Lecturer, Atal Bihari Vajpayee Hindi University. E-mail: mahima.mang@gmail.com

***Correspondence:** mahima.mang@gmail.com

Submitted: 02 Feb 2013 | Revised: 17 July 2013 | Accepted: 24 Nov 2013 | Published: 12 Dec 2013

सारांश: ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता और **1947** में उपमहाद्वीप के विभाजन के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव उभरने लगा। जम्मू और कश्मीर पर नियंत्रण का प्रश्न दोनों देशों के बीच प्रथम युद्ध (**1947–1948**) का केंद्र बना। यह अध्ययन युद्ध की सीमित प्रकृति का विश्लेषण उसके राजनीतिक उद्देश्यों, भौगोलिक विस्तार और सैन्य संसाधनों के आधार पर करता है। अध्ययन के अनुसार, यह आधुनिक युद्धों के शुरुआती उदाहरणों में से एक था, जिसमें पाकिस्तान ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जम्मू और कश्मीर में सशस्त्र विद्रोह को संगठित करने और बढ़ावा देने की रणनीति अपनाई। स्पष्ट सैन्य सिद्धांत और पूर्व अनुभव की कमी के कारण इस रणनीति को सीमित सफलता मिली। फिर भी, इस अनुभव ने पाकिस्तान को बाद के युद्धों में विरोधी पक्ष की अग्रिम पंक्ति के पीछे विद्रोही समूहों और अनियमित सशस्त्र बलों पर निर्भर रहने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रमुख शब्द — भारत, पाकिस्तान, भारत का विभाजन, जम्मू और कश्मीर, असमंजित युद्ध, पश्तून (पठान) जनजातीय लड़ाके, आज़ाद कश्मीर।

Abstract: Following independence from British rule and the partition of the subcontinent in 1947, political tensions began to emerge between India and Pakistan. The question of control over Jammu and Kashmir became the central issue in the first war (1947–1948) between the two nations. This study analyzes the limited nature of the conflict, examining it through the lenses of its political objectives, geographical scope, and military resources. According to the study, this conflict served as an early example of modern warfare, in which Pakistan adopted a strategy of organizing and fostering an armed insurgency in Jammu and Kashmir to achieve its political goals. Due to a lack of clear military doctrine and prior experience, this strategy met with only limited success. Nevertheless, the experience encouraged Pakistan to rely on insurgent groups and irregular armed forces—operating behind the adversary's front lines—in subsequent conflicts.

Keywords: India, Pakistan, the partition of India, Jammu and Kashmir, asymmetric warfare, Pashtun (Pathan) tribal fighters, Azad Kashmir.

1. प्रस्तावना

भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध ब्रिटिश भारत के विभाजन के कुछ ही महीनों के भीतर आरंभ हुआ। संघर्ष का केंद्र जम्मू और कश्मीर की तत्कालीन रियासत थी, जिसकी राजनीतिक स्थिति को लेकर दोनों नवस्वतंत्र राज्यों के दावे परस्पर विरोधी थे। रियासत के भीतर पहले से मौजूद राजनीतिक तनाव, विभाजन के दौरान फैली हिंसा, स्थानीय विद्रोह और सीमापार से आए सशस्त्र समूहों की भागीदारी ने संकट को गहरा किया। भारत की सैन्य भागीदारी और बाद में पाकिस्तानी नियमित इकाइयों की तैनाती ने इस संकट को अंतरराज्यीय युद्ध में बदल दिया।

युद्ध के सीमित स्वरूप को तीन स्तरों पर समझा जा सकता है। राजनीतिक उद्देश्यों का केंद्र जम्मू और कश्मीर था। मुख्य लड़ाई रियासत के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रित रही। दोनों पक्षों के पास स्वतंत्रता के तुरंत बाद संसाधन जुटाने और दुर्गम क्षेत्रों में उन्हें बनाए रखने की सीमित क्षमता थी। फिर भी रियासत की राजनीतिक स्थिति, नागरिक आबादी और भारत–पाकिस्तान संबंधों पर युद्ध के प्रभाव दीर्घकालिक रहे।

यह रूपांतर तीन प्रश्नों पर केंद्रित है। रियासत की राजनीतिक स्थिति सैन्य संघर्ष में कैसे बदली? भूगोल, रसद और सशस्त्र समूहों की बदलती भूमिका ने युद्ध के घटनाक्रम को कैसे प्रभावित किया? युद्धविराम के बाद क्षेत्रीय नियंत्रण और राजनीतिक दावों के बीच क्या संबंध बना? विवेचन किस के अध्ययन, उसमें उद्धृत भारतीय और पाकिस्तानी विवरणों तथा संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज़ों पर आधारित है। सैन्य संस्मरण अपने लेखकों की भूमिका और दृष्टिकोण दर्शाते हैं। जहाँ पक्षों के विवरण अलग हैं, वहाँ उनकी तुलना विशेष महत्त्व रखती है।

2. विभाजन और जम्मू-कश्मीर विवाद की उत्पत्ति

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने औपनिवेशिक शासन समाप्त करने की प्रक्रिया को गति दी। अगस्त 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन से भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र डोमिनियन बने। ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति के साथ रियासतों के भारत या पाकिस्तान में अधिमिलन का प्रश्न सामने आया। जम्मू और कश्मीर में महाराजा हरि सिंह शासन कर रहे थे और रियासत की आबादी में मुसलमान बहुसंख्यक थे। रियासत में क्षेत्रीय, भाषाई और धार्मिक विविधता थी। इस कारण उसकी राजनीतिक आकांक्षाओं को किसी एक समुदाय या क्षेत्र की स्थिति के आधार पर समझना

© 2013 By the Authors. This Open Access Article Was Published Under a Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

कठिन है।

महाराजा ने प्रारंभ में अधिमिलन का निर्णय टाला। रियासत की प्रमुख व्यापारिक और परिवहन कड़ियाँ उन इलाकों से होकर जाती थीं जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में आ गए। किस के अनुसार, व्यापार और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में व्यवधान ने महाराजा के प्रशासन पर दबाव बढ़ाया। इस आर्थिक निर्भरता को समझना आवश्यक है क्योंकि राजनीतिक निर्णय ऐसे समय लिए जा रहे थे जब सामान्य प्रशासन, आवागमन और आपूर्ति भी अनिश्चित हो गए थे।

पंजाब में विभाजन के दौरान व्यापक सांप्रदायिक हिंसा और विस्थापन ने जम्मू और कश्मीर को भी प्रभावित किया। पुंछ में अगस्त 1947 के दौरान राज्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह उभरा। इस क्षेत्र में स्थानीय शिकायतों और पूर्व सैनिकों की मौजूदगी ने विद्रोह की प्रकृति को प्रभावित किया। किस स्थानीय विद्रोह के साथ सीमापार समर्थन पर बल देते हैं। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में भारतीय आरोपों का खंडन किया और अधिमिलन की वैधता पर आपत्ति जताई। अकबर खान के संस्मरण में कुछ पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों की भूमिका का विवरण मिलता है, हालांकि उच्चतम राजनीतिक स्तर पर निर्णय किस प्रकार लिए गए, इस पर स्रोतों में अनिश्चितता बनी रहती है (Khan, 1970; Dasgupta, 2002; संयुक्त राष्ट्र, 1989)।

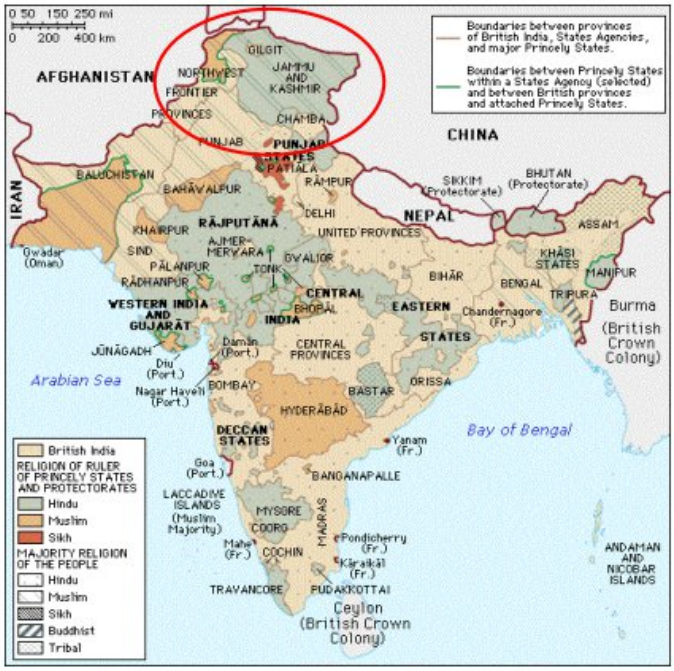


Figure 1. India and Pakistan after August 15, 1947. The red oval marks Jammu and Kashmir. Source: http://www.oberlin.edu/faculty/svolk/367f07syllabus-main.htm

3. भूगोल, संसाधन और सैन्य संगठन

रियासत का भूगोल युद्ध को समझने की कुंजी है। उत्तर में गिलगित और बाल्टिस्तान, पूर्व में लद्दाख, मध्य में कश्मीर घाटी और दक्षिण में जम्मू के भूभाग की परिस्थितियाँ अलग थीं। ऊँची पर्वत शृंखलाओं, कम संख्या में दर्रों और सीमित सड़क संपर्क ने इन क्षेत्रों को एक-दूसरे से अलग किया। कश्मीर घाटी में श्रीनगर राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण था। जम्मू दक्षिणी क्षेत्र का प्रमुख केंद्र था। लेह और स्कर्दू के बीच तथा लद्दाख और कश्मीर घाटी के बीच संपर्क मौसम और ऊँचाई से प्रभावित होता था।.



Figure 2. The original borders and current partition of Jammu and Kashmir. Source: Central Intelligence Agency, Langley, 2003

ऊँचाई और ठंड ने सैनिकों की आवाजाही, संचार और सामग्री की ढुलाई को बाधित किया। कम क्षमता वाले पुल और खराब सड़कें भारी साधनों के उपयोग को सीमित करती थीं। भारत से कश्मीर घाटी तक स्थल संपर्क में बनिहाल दर्रे का महत्त्व था। लद्दाख की ओर ज़ोजिला का रास्ता विशेष रूप से कठिन था। श्रीनगर के हवाई अड्डे ने प्रारंभिक भारतीय तैनाती संभव बनाई और पुंछ तथा लेह की अस्थायी हवाई पट्टियों ने बाद में दूरस्थ मोर्चों को समर्थन दिया। घाटी, जम्मू और लद्दाख में एक साथ दबाव बढ़ने पर किसी एक क्षेत्र की प्राथमिकता तय करने का असर दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ता था।

ब्रिटिश भारतीय सेना का विभाजन युद्ध की पृष्ठभूमि का हिस्सा था। किस के विवरण में सैनिकों और सैन्य सामग्री का लगभग दो-तिहाई हिस्सा भारत और एक-तिहाई पाकिस्तान को आवंटित होना था। प्रशिक्षण केंद्रों, भंडारों और मरम्मत सुविधाओं का वितरण असमान था। दोनों देशों के सैन्य नेतृत्व में उस समय ब्रिटिश अधिकारी भी मौजूद थे। भारत को अपेक्षाकृत अधिक नियमित इकाइयाँ और प्रशासनिक संसाधन मिले, लेकिन विभाजन ने उसकी इकाइयों को भी पुनर्गठित होने पर मजबूर किया। पाकिस्तान की नियमित सेना भी गठन और पुनर्तैनाती की प्रक्रिया से गुजर रही थी (भारत सरकार, 1987; Barua, 2005)।

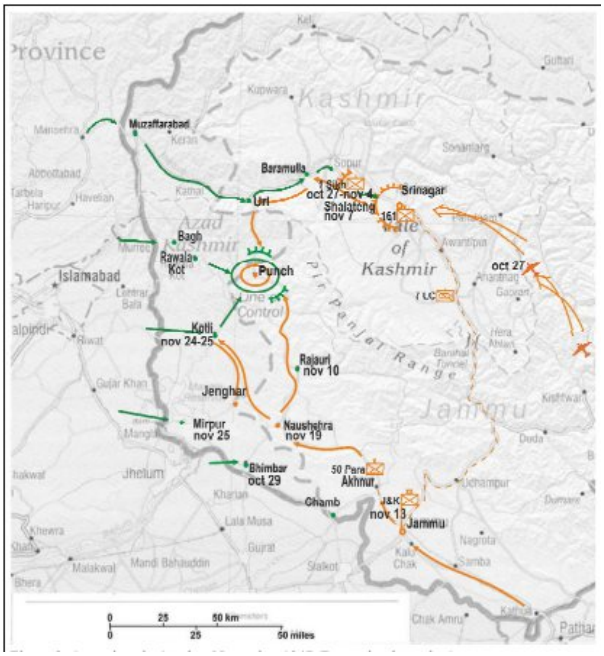


Figure 3. Operations in October-November 1947 (Drawn by the author)

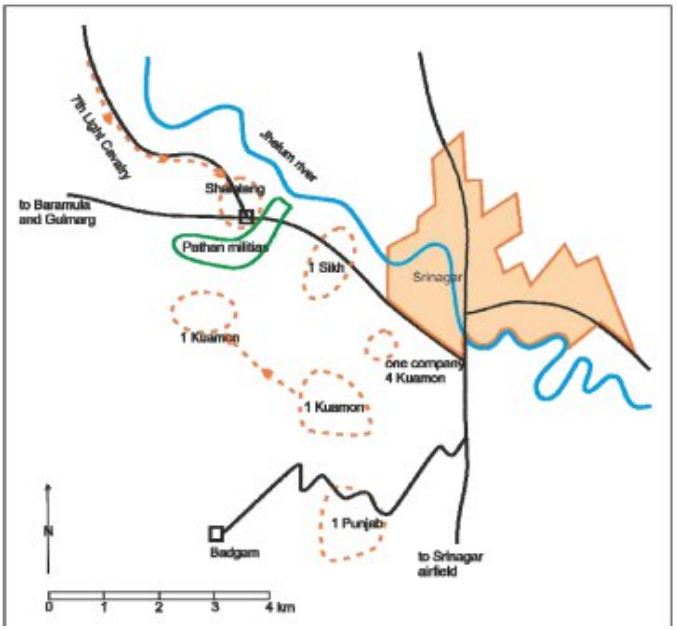


Figure 4. Battle of Shalateng, November 7 1947. (Drawn by the author)

लड़ाई में रियासत की अपनी सेनाएँ, भारत और पाकिस्तान की नियमित इकाइयाँ, पुंछ तथा अन्य क्षेत्रों से जुड़े स्थानीय सशस्त्र समूह और उत्तर-पश्चिम से आए पश्तून जनजातीय लड़ाके शामिल थे। स्रोत में 'लश्कर' शब्द जनजातीय लड़ाकों के संगठित दलों के लिए प्रयुक्त हुआ है। स्थानीय बलों की प्रेरणाएँ और नेतृत्व अलग-अलग थे। इसलिए पाकिस्तानी नियमित सेना, आज़ाद कश्मीर से संबद्ध बलों और जनजातीय दलों की भूमिकाओं को अलग-अलग देखना आवश्यक है।

4. युद्ध का घटनाक्रम

4.1 पुंछ का विद्रोह और अक्टूबर 1947 का संकट

पुंछ के विद्रोह और सीमावर्ती हिंसा के बीच रियासत की सेना पर कई स्थानों की रक्षा करने का दबाव बढ़ा। किस के अनुसार, सितंबर से सीमापार हमलों में वृद्धि हुई। 22 अक्टूबर को पश्तून जनजातीय दलों का बड़ा आक्रमण मुज़फ़्फ़राबाद और डोमेल की दिशा से कश्मीर घाटी की ओर बढ़ा। उड़ी में रियासती बलों के प्रतिरोध के बाद लड़ाई बारामूला की ओर पहुँची। जम्मू क्षेत्र में स्थानीय सशस्त्र समूहों की गतिविधियों से पुंछ और अन्य इलाकों में भी स्थिति बिगड़ी। 24 अक्टूबर को मुहम्मद इब्राहीम के नेतृत्व में आज़ाद कश्मीर सरकार के गठन की घोषणा हुई। इस घटनाक्रम ने रियासत के शासन पर परस्पर विरोधी दावों को और स्पष्ट किया।

किस के अनुसार बारामूला में हुई हिंसा और आगे बढ़ने में देरी से श्रीनगर में भारतीय हस्तक्षेप के लिए समय मिला। जनजातीय लड़ाकों के व्यवहार का आकलन करते समय स्रोतों की प्रकृति और नागरिकों पर हुए प्रभाव, दोनों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सैन्य संस्मरण जहाँ इकाइयों की गतिविधियों पर केंद्रित हैं, वहीं नागरिकों के अनुभवों का पूरा विवरण उनमें सीमित है।

4.2 अधिमिलन और श्रीनगर की रक्षा

भारतीय विवरण के अनुसार महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ अधिमिलन-पत्र पर हस्ताक्षर किए। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना की पहली टुकड़ियाँ हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुँचीं। भारत ने अधिमिलन को अपनी सैन्य भागीदारी का आधार माना। पाकिस्तान ने उसकी वैधता को चुनौती दी। इस प्रकार श्रीनगर का तत्काल सैन्य संकट रियासत की राजनीतिक स्थिति के व्यापक प्रश्न से जुड़ गया (भारत सरकार, 1987; Gupta, 1966; Lamb, 1991)।

नवंबर की शुरुआत में श्रीनगर के निकट बड़गाम और शालातेंग में लड़ाई हुई। 7 नवंबर को शालातेंग की लड़ाई ने घाटी में तत्काल सैन्य संतुलन बदल दिया। इसके बाद भारतीय बलों ने बारामूला और उड़ी पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया। श्रीनगर का बचाव भारत की सैन्य उपस्थिति के लिए निर्णायक था, लेकिन जम्मू, पुंछ और उत्तरी क्षेत्रों में संघर्ष जारी रहा। नवंबर के अंत में मीरपुर पर आज़ाद कश्मीर से जुड़े बलों का नियंत्रण स्थापित हुआ। मूल अध्ययन वहाँ हिंदू और सिख नागरिकों के विरुद्ध गंभीर हिंसा का उल्लेख करता है (Sen, 1969; भारत सरकार, 1987)।

4.3 शीतकालीन संघर्ष और 1948 के वसंत की लड़ाई

दिसंबर 1947 से वसंत 1948 तक जम्मू क्षेत्र में झंगड़, नौशेरा और राजौरी के आसपास संघर्ष जारी रहा। मौसम और पर्वतीय भूभाग ने घाटी तथा लद्दाख की दिशा में आवाजाही सीमित की। पुंछ की घेराबंदी के दौरान एक अस्थायी हवाई पट्टी से नागरिकों और सैनिकों तक सहायता पहुँचाई गई। दिसंबर 1947 से हवाई आपूर्ति ने वहाँ की रक्षा जारी रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वसंत के दौरान भारतीय सेना ने झंगड़ और राजौरी की दिशा में नियंत्रण पुनः स्थापित किया। मूल अध्ययन राजौरी पर पुनः नियंत्रण की तिथि 12 अप्रैल 1948 देता है।

उत्तर में गिलगित की राजनीतिक और सैन्य स्थिति पहले ही बदल चुकी थी। स्कर्दू और लेह पर दबाव बढ़ने से लद्दाख में भारतीय उपस्थिति बनाए रखने का प्रश्न अधिक गंभीर हो गया। मई 1948 में लेह की हवाई पट्टी पर परिवहन विमान के उतरने से इस क्षेत्र में आपूर्ति और सैनिक सहायता की संभावना बढ़ी। इसके बाद भी भूगोल और मौसम ने उत्तर के मोर्चे पर निर्णायक बढ़त हासिल करना कठिन बनाए रखा (भारत सरकार, 1987; Vas, 1987)।

4.4 नियमित सेनाओं की बढ़ती भूमिका और अंतिम अभियान

1948 के मध्य तक पाकिस्तानी नियमित इकाइयाँ लड़ाई में अधिक प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गईं। भारतीय सेना ने भी अपने कमान ढाँचे को पुनर्गठित किया और जम्मू तथा श्रीनगर की दिशाओं में अलग-अलग सैन्य ज़िम्मेदारियाँ निर्धारित कीं। स्थानीय और जनजातीय समूहों की भूमिका बनी रही। फिर भी युद्ध का संचालन अब अधिक स्पष्ट रूप से दोनों देशों की नियमित सेनाओं से प्रभावित होने लगा।

उत्तर में 1948 के दौरान कारगिल और द्रास पर नियंत्रण बदला। लंबी घेराबंदी के बाद 14 अगस्त को स्कर्दू का पतन हुआ। लेह में भारतीय बलों ने अपनी स्थिति बनाए रखी। 1 नवंबर को भारतीय सेना ने ज़ोजिला में बढ़त बनाई और उसके बाद द्रास तथा कारगिल की ओर आगे बढ़ी। नवंबर के अंत में लेह की दिशा से आने वाले बलों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। लगभग इसी समय जम्मू क्षेत्र में भारतीय सेना ने पुंछ से स्थल संपर्क फिर स्थापित किया। इन अभियानों ने वर्ष के अंत में दोनों पक्षों की स्थिति को प्रभावित किया, लेकिन पूरी रियासत किसी एक पक्ष के नियंत्रण में नहीं आई (Bajwa, 2003; भारत सरकार, 1987)।

5. संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और युद्धविराम

भारत ने जनवरी 1948 में जम्मू और कश्मीर का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष रखा। भारत ने सीमापार से आए लड़ाकों को पाकिस्तानी सहायता का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने आरोपों से इनकार किया और अधिमिलन को चुनौती दी। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 39 ने भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना की। 21 अप्रैल 1948 के प्रस्ताव 47 ने आयोग का विस्तार किया और शांति एवं व्यवस्था बहाल करने तथा जनमत-संग्रह के लिए शर्तों का ढाँचा सुझाया। सैनिकों की वापसी, बलों में कमी और इन कदमों के क्रम पर दोनों पक्षों के मतभेदों ने प्रस्तावों के कार्यान्वयन में बाधा डाली।

1 जनवरी 1949 को युद्धविराम लागू हुआ। युद्धविराम के समय दोनों पक्षों ने अलग-अलग क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखा। जुलाई 1949 के कराची समझौते ने युद्धविराम रेखा निर्धारित की। बाद में 1971 की लड़ाई के पश्चात 2 जुलाई 1972 के शिमला समझौते में नियंत्रण रेखा की परिभाषा तय हुई। इस कालक्रम में 1949 की युद्धविराम रेखा और 1972 की नियंत्रण रेखा दो अलग ऐतिहासिक व्यवस्थाएँ हैं (संयुक्त राष्ट्र, 1989; OIOS, 2022)।

6. युद्ध का आकलन

6.1 स्थानीय सशस्त्र समूह और नियमित बल

किस युद्ध के पहले चरण में गैर-राज्य सशस्त्र समूहों की भूमिका को विशेष महत्व देते हैं। जनजातीय लड़ाकों और स्थानीय बलों की भागीदारी ने रियासत की सेना पर अलग-अलग क्षेत्रों में दबाव डाला। इनके नेतृत्व, प्रशिक्षण और अनुशासन में भिन्नता थी। प्रारंभिक बढ़त के बावजूद वे श्रीनगर पर नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहे। किस इसे राजनीतिक उद्देश्य, उपलब्ध संसाधनों और विभिन्न बलों के समन्वय के बीच असंगति का परिणाम मानते हैं। बाद में नियमित इकाइयों की बढ़ती भागीदारी से लड़ाई की संरचना बदली, हालांकि स्थानीय समूह पूरी तरह

अलग नहीं हुए (Khan, 1970; Kiss, मूल अध्ययन)।

भारतीय पक्ष ने श्रीनगर हवाई अड्डे के उपयोग, घाटी में नियमित बलों की तैनाती और हवाई आपूर्ति से लाभ उठाया। उड़ी के बाद जम्मू, पुंछ और लद्दाख में एक साथ बढ़ते दबाव के कारण भारतीय संसाधन कई मोर्चों में बँटे। किस इसे भारतीय प्राथमिकताओं की एक प्रमुख दुविधा मानते हैं। पैदल सेना दोनों पक्षों के लिए केंद्रीय रही। तोपखाने और बख़्तरबंद इकाइयों का उपयोग कुछ लड़ाइयों में महत्त्वपूर्ण था, जबकि हवाई परिवहन ने घिरे या दूरस्थ क्षेत्रों में सैनिक सहायता और आपूर्ति बनाए रखने में योगदान दिया।

6.2 नागरिक क्षति और स्रोतों की सीमाएँ

मूल अध्ययन भारतीय सशस्त्र बलों में लगभग 1,500 मृतकों और 3,500 घायलों का अनुमान देता है। इन संख्याओं को उसी अध्ययन में उद्धृत अनुमान के रूप में पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान की ओर से लड़ने वाले नियमित और अनियमित बलों के लिए तुलनीय अभिलेख उपलब्ध न होने से सैन्य हताहतों की समग्र तुलना कठिन है। विभाजन और युद्ध के दौरान नागरिकों को हत्या, विस्थापन और संपत्ति की हानि का सामना करना पड़ा। बारामूला और मीरपुर जैसे स्थानों पर हुई हिंसा का उल्लेख स्रोतों में मिलता है, लेकिन पूरे क्षेत्र की नागरिक क्षति का विश्वसनीय कुल आँकड़ा मूल अध्ययन में उपलब्ध नहीं है।

6.3 ब्रिटिश प्रभाव और युद्ध की सीमाएँ

स्वतंत्रता के शुरुआती महीनों में दोनों डोमिनियनों की सेनाओं में ब्रिटिश अधिकारी उच्च पदों पर बने रहे। सैन्य सामग्री के बँटवारे और कमान के संक्रमण के साथ ब्रिटिश सरकार की कूटनीतिक भूमिका भी महत्त्वपूर्ण थी। किस ब्रिटिश प्राथमिकताओं को युद्ध का विस्तार सीमित रखने की कोशिश से जोड़ते हैं। वे यह भी दर्ज करते हैं कि कई भारतीय और पाकिस्तानी स्रोत ब्रिटिश अधिकारियों पर एक-दूसरे का पक्ष लेने का आरोप लगाते हैं। इन आरोपों से स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश भूमिका का मूल्यांकन करते समय अधिकारियों के निर्णय, लंदन की नीति और दोनों नवस्वतंत्र सरकारों की अपनी प्राथमिकताओं को अलग-अलग देखना चाहिए (Dasgupta, 2002; Kiss, मूल अध्ययन)।

7. असममित युद्ध की व्याख्या

किस प्रथम भारत–पाकिस्तान युद्ध को असममित युद्ध के इतिहास में एक प्रारंभिक उदाहरण मानते हैं। उनकी व्याख्या में शुरुआती चरण की विशेषता यह थी कि स्थानीय विद्रोह, बाहरी जनजातीय लड़ाके और राज्य-समर्थन से जुड़े प्रयास नियमित सैन्य हस्तक्षेप के साथ अलग-अलग समय पर जुड़े। युद्ध के बाद के चरण में नियमित सेनाओं का प्रभाव बढ़ा। इसलिए पूरे युद्ध की व्याख्या के लिए स्थानीय राजनीतिक असंतोष, दोनों राज्यों की नीतियों और नियमित सैन्य अभियानों को एक साथ समझना आवश्यक है।

मूल अध्ययन इस अनुभव को 'चौथी पीढ़ी के युद्ध' की अवधारणा से जोड़ता है। इस अवधारणा का उपयोग बाद की सैन्य बहसों में हुआ और इसे 1947–1948 के संघर्ष पर पीछे से लागू किया गया है। इसकी सहायता से नियमित और अनियमित बलों के संबंध पर विचार किया जा सकता है। किस का यह तर्क कि शुरुआती अनुभव ने पाकिस्तान की बाद की नीतियों को प्रभावित किया, एक ऐतिहासिक व्याख्या है। बाद के संघर्षों के अलग राजनीतिक संदर्भों को देखते हुए इस संबंध का आकलन प्रत्येक मामले के साक्ष्यों के आधार पर करना उचित है (Kiss, 2009; Strachan, 2007; Swami, 2006)।

8. निष्कर्ष

प्रथम भारत–पाकिस्तान युद्ध विभाजन के बाद जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक स्थिति को लेकर उभरे संकट से विकसित हुआ। पुंछ के विद्रोह, सीमापार से आए लड़ाकों, अधिमिलन और दोनों देशों की सैन्य भागीदारी ने संघर्ष के स्वरूप को क्रमशः बदला। घाटी, जम्मू और लद्दाख के बीच भौगोलिक विभाजन, सीमित स्थल संपर्क तथा हवाई आपूर्ति की उपलब्धता ने युद्ध की दिशा और उसकी सीमाएँ निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

युद्ध का राजनीतिक परिणाम जनवरी 1949 के युद्धविराम में दिखाई देता है। लड़ाई समाप्त होने पर रियासत के अलग-अलग क्षेत्रों पर दोनों पक्षों का नियंत्रण बना रहा और राजनीतिक स्थिति पर सहमति नहीं बनी। युद्ध का ऐतिहासिक महत्त्व इस अंतर में निहित है कि क्षेत्रीय नियंत्रण का तत्काल प्रश्न सैन्य और कूटनीतिक व्यवस्थाओं से स्थिर हुआ, जबकि अधिमिलन और जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक स्थिति पर मतभेद भारत–पाकिस्तान संबंधों का हिस्सा बने रहे।

References

[1]. Operations In Jammu and Kashmir 1947-1948. Ministry of Defence, Government of India.

Thomson Press (India) Limited, New Delhi. 1987.

Abbas, Hassan: Pakistan's Drift into Extremism: Allah, the Army, and America's War on

Terror, M.E. Sharpe, New York, 2005. ISBN 978-0-7656-1496-4.

Ali, Syed: "The Perils of Covert Coercion," in: Freedman Lawrence: Strategic Coercion –

Concepts and Cases, Oxford University Press, Oxford, 1998. ISBN 0-19-829349-6.

Amin, Agha Humayun: "The Pakistan Army till 1965," Strategicus and Tacticus, Lahore,

1999.

Amin, Agha Humayun: "The war of lost opportunities," Defence Journal, Karachi, April and

May 2000.

Ankit, Rakesh: "The Cold War and its Impact on the Evolution of the Kashmir Crisis, 1947-

48," Journal of the Oxford University History Society, St. Hilda's College, Oxford, 2009.

Bajwa, Kuldip Singh: Jammu and Kashmir War, 1947-1948: political and military

perspective, Har Anand Publications, New Delhi, 2003

Barua, Pradeep: The state at War in South Asia, University of Nebraska, Lincoln, 2005.

ISBN, 978-0-8032-1344-9.

Cohen, Maurice: Thunder Over Kashmir, Orient Longman Ltd, Hyderabad, 1955. ISBN 81-

250-0016.

Dasgupta, Chandrashekhar: War and Diplomacy in Kashmir, 1947-48, Sage Publications,

New Delhi, 2002. ISBN 0-7619-9588-9.

Goel, Sita Ram: Muslim Separatism – Causes and Consequences, Voice of India, New Delhi,

s.a.

Gupta, Sisir: Kashmir – a Study in India-Pakistan Relations, Asia Publishing House, London,

1966.

Khan, Muhammad Akbar: Raiders in Kashmir, 160 p. Jang Publisher's, Lahore, 1970. ISBN

969-36-0025-8.